

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :- 182/2023

घेवर चन्द भाटी

—अपीलार्थी

## बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर, (लेंड रिकॉर्ड्स), पाली।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.08.2024

## उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुशील सोलंकी, अधिवक्ता  
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)  
असलम मेहर, सदस्य

## आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किए हैं कि अपीलार्थी पटवारी के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी के विरुद्ध एफआईआर संख्या 308/2021 दिनांक 13.08.2021 को दर्ज हुई थी। उसके पश्चात अपीलार्थी के विरुद्ध चार्जशीट दिनांक 14.12.2021 को न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 25.08.2021 के द्वारा निलंबित किया गया। बाद में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 29.08.2023 के द्वारा बहाल किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी भू अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए समस्त अर्हता पूरी करता था। आदेश दिनांक 02.12.2021 के द्वारा पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति निर्णय को बंद लिफाफे में रखा गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को रिक्ति दिनांक 01.04.2021 के विरुद्ध पदोन्नति प्रदान किए जाने पर विचार किया गया था। इस प्रकार अपीलार्थी दिनांक 01.04.2021 की रिक्ति के विरुद्ध जब पदोन्नति योग्य पाया जाता है तो इस आधार पर अपीलार्थी के संबंध में पदोन्नति आदेश लंबित नहीं रखा जा सकता कि अपीलार्थी के विरुद्ध बाद में एफआईआर दर्ज है। एफआईआर रिक्ति दिनांक के पश्चात दर्ज हुई है। अपीलार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के न्यायिक दृष्टांत एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5194/20212 दुली चंद गुर्जर बनाम न्यूक्लीयर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.01.2015 प्रस्तुत किया है, जिसमें यह माना गया है कि जिस दिनांक को याची एसीपी प्राप्त करने का अधिकारी हुआ है, यदि

उस दिनांक को उसके विरुद्ध कोई चार्जशीट नहीं थी तो याची को एसीपी का लाभ दिया जाये। अपीलार्थी ने वर्ष 2021-22 की रिक्तियों के विरुद्ध भू अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान किए जाने के निर्देश दिए जाने की प्रार्थना की है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी ने द्वितीय प्रार्थना सिलेक्शन स्केल प्राप्त करने की है, जो अपीलार्थी को प्राप्त हो चुकी है। ऐसे में अपीलार्थी द्वितीय प्रार्थना के संबंध में इस अपील को not press करता है।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता का कथन है कि वर्ष 2021-22 की रिक्तियों के विरुद्ध डीपीसी दिनांक 02.12.2021 को हुई थी, तब तक अपीलार्थी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो चुकी थी और चार्जशीट भी प्रस्तुत की जा चुकी थी। इस कारण से अपीलार्थी के संबंध में पदोन्नति निर्णय बंद लिफाफे में रखा गया। अपीलार्थी को पदोन्नति के लिए दिनांक 01.04.2021 की रिक्तियों के विरुद्ध विचार में रखा गया है और इस दिनांक को अपीलार्थी के विरुद्ध कोई फौजदारी प्रकरण दर्ज नहीं था। ऐसे में अपीलार्थी के प्रकरण के संबंध में राजस्व मंडल से मार्गदर्शन चाहा गया है।
3. हमने उभयपक्षों के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी को भू अभिलेख निरीक्षक के पद पर वर्ष 2021-22 की रिक्तियों के विरुद्ध दिनांक 01.04.2021 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति पर विचार किया गया था। दिनांक 01.04.2021 तक अपीलार्थी के विरुद्ध कोई फौजदारी प्रकरण दर्ज नहीं था। ऐसे में रिक्ति दिनांक के पश्चात दर्ज फौजदारी प्रकरण के आधार पर अपीलार्थी की पदोन्नति की कार्यवाही को बंद लिफाफे में रखा जाना उचित नहीं है। राज्य सरकार के द्वारा परिपत्र आदेश दिनांक 04.06.2008 के बिन्दु संख्या 12.13 के (i) में निर्देश है कि *विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किसी भी विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष में पदोन्नति हेतु विचार करते समय पदोन्नति के पात्र राजसेवकों के विरुद्ध लंबित अनुशासनिक कार्यवाही/फौजदारी प्रकरण/दण्डादेश/निलंबन की स्थिति का आकलन उस स्थिति के संदर्भ में किया जायेगा जिस रिक्ति के विरुद्ध राजसेवक पद हेतु विचारार्थ है, अर्थात् राजसेवक जिस रिक्ति के विरुद्ध चयनित होता है उस रिक्ति की उपलब्धता जिस दिवस को होती है, उस दिवस तक की स्थिति में राजसेवक के विरुद्ध लंबित अनुशासनिक कार्यवाही/फौजदारी प्रकरण/ दण्डादेश/निलंबन इत्यादि पर विभागीय पदोन्नति समिति को विचार करना होगा।* इस मामले के समान तथ्यों पर आधारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरणों की ओर अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया, जो निम्न प्रकार है :-

1. **Union of India etc. V/s K.V.Jankiraman etc. on 27.08.1991, 1991 A.I.R. 2010, 1991 SCR(3) 790**
2. **R.P.Singh V/s Union of India Civil Appeal No. 2605 of 2013 (arising out of SLP (c) No. 16797/2012)**
3. **Harsh Kumar Sharma V/s State of Punjab & anr Civil Appeal No. 11231-32 of 2016**
4. **Union of India V/s A.N.mohnan Appeal (Civil) 2020 of 2007**
5. **S.B.Civil Writ Petition No. 17238/2015 Kailash Chand Bohra V/s State of Rajasthan**
6. **S.B.Civil Writ Petition No. 15429/2019 Banshi Lal V/s State of Rajasthan**
7. **S.B.Civil Writ Petition No. 15788/2019 Khan Mohd. V/s State of Rajasthan & Ors.**
8. **S.B.Civil Writ Petition No. 15499/2019 Ravindra Kumar Yadav V/s State of Rajasthan & Ors.**
9. **S.B.Civil Writ Petition No. 6433/2021 Gopal Lal V/s State of Rajasthan & Ors.**
10. **S.B.Civil Writ Petition No. 6690/2021 Brij Mohan V/s Managing Committee & Ors.**
11. **S.B.Civil Writ Petition No. 11745/2017 Jay Singh Shekhawat V/s State of Rajasthan & Ors.**
12. **S.B.Civil Writ Petition No. 18074/2018 Sandeep Kumar Barar V/s State of Rajasthan & Ors.**

उपरोक्त मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लंबित मामलों के आधार पर कार्मिकों की पदोन्नतियों को रोका जाना अनुचित माना है। इस प्रकार अपीलार्थी भी उक्त मामलों के आधार पर पदोन्नति प्राप्त करने का हकदार है। S.B.Civil Writ Petition No. 18074/2018 Sandeep Kumar Barar V/s State of Rajasthan & Ors. वाले मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.03.2022 को निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है :-

*"Similar orders passed by the Department in the case of Shri Dinesh M.N., IPS and Shri A. Ponnuchamy, IPS are also reproduced for ready reference :*

*"Shri Dinesh M.N., IPS (RJ:1995), Managing Director, RAJSICO is hereby promoted in the Selectdion Grade (Pay Band-4: Rs. 37400-67000; plus Grade Pay Rs. 8700). Grade of the Deputy Inspector General of Police (Pay Band: Rs. 37400-67000 plus Grade Pay Rs. 8900) and Grade of the Inspector General of Police (Pay Band: Rs. 37400-67000 plus Grade Pay Rs. 10000) of Indian Police Service with effect from 09.05.2014. The said scales/grades are granted subject to the outcome of all pending criminal proceedings against him."*

*"Shri A. Ponnuchamy, IPS (RJ:1991) is hereby promoted in the Grade of Additional Director General of Police (HAG Rs. 67000-79000) of Indian Police Service with effect from 27.10.2016 i.e. date of reinstatement in service subject to the outcome of all pending criminal proceedings against him."*

*In view of the above mentioned orders, it is clear that it has been a regular practice of the Department to promote the police officials subject to the decision of the criminal proceedings pending against them. Therefore, on the sole ground of discrimination, the present writ petition of the petitioner deserves to be allowed.*

*For the reasons discussed above, the writ petition succeeds and is hereby allowed. The respondents are directed to open the sealed cover pertaining to the recommendation of the screening meeting qua the petitioner. If the petitioner has been recommended for promotion, he be accorded promotion which shall be subject to the outcome of the criminal proceedings pending against him. The required orders be passed within a period of one month from the date of receipt of the copy of the present order."*

5. अतः हम पाते हैं कि अपीलार्थी के संबंध में रिक्ति उपलब्ध होने की दिनांक तक पदोन्नति दिए जाने का आकलन इसी संदर्भ में किया जाएगा कि अपीलार्थी के विरुद्ध उस दिनांक तक कोई एफआईआर दर्ज है या नहीं। उपरोक्त परिपत्र में दिए गए निर्देशानुसार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दिए गए न्यायिक निर्णयों के आधार पर हम पाते हैं कि अपीलार्थी की पदोन्नति को रोका जाना उचित नहीं है।
6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी की पदोन्नति के संबंध में शीलबंद लिफाफे को खोला जाए एवं यदि अपीलार्थी पदोन्नति के लिए पात्र पाया जाता है तो अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जाए।

(असलम मेहर)  
सदस्य

(अनन्त भंडारी)  
सदस्य(न्यायिक)